

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2022—चैत्र 18, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 फरवरी 2022

क्रमांक आर-318/2022/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती आर शंगीता, भा.प्र.से. (सी.जी.:2005) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वन विभाग तथा सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-03/2020/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (HAG+ : Level 16 in the Pay Matrix Rs. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री एस. एस. बजाज (1988)
2. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश सोनकर, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मार्च 2022

क्रमांक एफ 10-8/2014/16.—“भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” (केन्द्रीय अधिनियम, 1996 का 27) की धारा 40 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के परामर्श पश्चात्, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन करती है. यह संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील तथा प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाकर निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है अर्थात् :—

प्रारूप अट्ठाईस
[नियम 272 (1) देखिये]

हितग्राही के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

भाग — 1

सामान्य विवरण

कार्य का स्वरूप	<input type="text"/>	कार्य की प्रकृति 1	<input type="text"/>	कार्य की प्रकृति 2	<input type="text"/>	कार्य की प्रकृति 3	<input type="text"/>
नाम	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम	<input type="text"/>	लिंग	<input type="text"/>		
वैवाहिक स्थिति	<input type="text"/>	जन्मतिथि	<input type="text"/>	आयु	<input type="text"/>	जाति	<input type="text"/>

☐

मनरेगा कर्मकार

पहचान विवरण —

(किसी भी एक पहचान की प्रविष्टि अनिवार्य है)

राशन कार्ड वोटर आईडी आर.एस.बी. वाय. आधार कार्ड

(बैंक की जानकारी अनिवार्य है)

बैंक का नाम शाखा का नाम खाता क्र.

आई.एफ.एस.सी. कोड ई.एस.आई.सी. नं. ई.पी.एफ.नं.

पता

वर्तमान पता

जिला विकासखंड/नगर निकाय
ग्रामीण शहरीय

स्थायी पता

जिला विकासखंड/नगर निकाय
ग्रामीण शहरीय

पंचायत ग्राम/वार्ड पंचायत ग्राम/वार्ड

वर्तमान पता वर्तमान ही स्थायी पता है. स्थायी पता

मो. नं. 1 मो. नं. 2

देय मोबाईल नंबर में प्राप्त ओटीपी नंबर

(नोट — ओटीपी के सत्यापन उपरांत ही भाग-01 फार्म पूर्ण माना जावेगा)

सुरक्षित करें

हितग्राही का आवेदन क्रमांक — 44835746 है.

भाग — 2

नाम	नियोजन का पता	उप स्थापना का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था	स्थापना का रजिस्ट्रीकरण क्र.	नियोजन के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख		उन दिनों की संख्या जिनमें वास्तविक रूप से नियोजन में रहा	टिप्पणी
				प्रारंभ तारीख	समाप्ति तारीख		
कुल योग							

नामिनी के नाम											
सदस्यों के नाम	हितग्राही से संबंध	जन्म तिथि	आयु	लिंग	आधार कार्ड नंबर	नामांकित	नाम निर्देशिती को भुगतान किए जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत	शैक्षणिक योग्यता	कक्षा	शैक्षणिक संस्था का नाम	वैवाहिक स्थिति

(नोट — नामिनी का नाम एवं 100 प्रतिशत करना अनिवार्य होगा)

सुरक्षित करें

हितग्राही का आवेदन क्रमांक — 44835746 है.**भाग — 3**

- (1) ऑनलाईन पंजीयन के लिए हितग्राहियों के लाईव फोटो अपलोड करना अनिवार्य है. अन्यथा हितग्राही पंजीकृत नहीं माना जायेगा अर्थात् हितग्राही योजना का लाभ लेने हेतु योग्य नहीं होगा. (फोटो की साइज 50KB से कम होना अनिवार्य है.

Live Camera	Captured Picture
Capture	Upload

- (2) पहचान स्वरूप दस्तावेज अपलोड की जानकारी —

राशन कार्ड	Choose file	No File Chosen
वोटर आईडी	Choose file	No File Chosen
आधार कार्ड	Choose file	No File Chosen
आयु प्रमाण पत्र	Choose file	No File Chosen

कृपया श्रम निरीक्षक/ट्रेड युनियन/नियोजक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज PDF में ही अपलोड करें.

श्रम निरीक्षक/ट्रेड युनियन/नियोजक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज	Choose file	No File Chosen
बैंक पासबुक दस्तावेज	Choose file	No File Chosen

कृपया बैंक पासबुक दस्तावेज Pdf में ही अपलोड करें.

नोट — समस्त अभिलेख मूल अभिलेख पहचान पत्र की स्कैन प्रति Pdf में ही अपलोड करें.
(पहचान पत्र की साइज 1 MB से कम होना अनिवार्य है)

कृपया कैपचा डाले	JEKDSJK

पीछे जाये

सुरक्षित करें

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 19-02/2012/25-2.—हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 7-2-2022 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर श्री मोहम्मद असलम खान, सदस्य का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री मोहम्मद असलम खान को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur, Atal Nagar

Raipur, the 7 March 2022

No. 2260/682/XXI-B/C.G./2022.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub rule (1) of Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, on the application for voluntary retirement of Shri Jagdamba Rai, Member of Chhattisgarh Higher Judicial Service and on the recommendation of the Hon'ble High Court of, Chhattisgarh through its memo no. 597/Confdl./2022/II-2-49/2001, dated 02-03-2022, the State Government of Chhattisgarh, hereby retires (Voluntarily) Shri Jagdamba Rai, Member of Chhattisgarh Higher Judicial Service from the post of District & Sessions Judge, Janjgir-Champa w.e.f. 28-2-2022 afternoon.

क्रमांक 2260/682/21-ब/छ.ग./2022.—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उप नियम (1) के खण्ड-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदम्बा राय, के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 597/Confdl./2022/II-2-49/2001, दिनांक 02-03-2022 द्वारा दी गई अनुशंसा पर, राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदम्बा राय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के पद से दिनांक 28-02-2022 अपराह्न से सेवा निवृत्त (स्वैच्छिक) करता है।

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 8 फरवरी 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1587/क/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	तुमान	2.117 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-03-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन तुमान नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत भूमि अर्जन
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	39
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	— लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	आवागमन की सुविधा हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 8 फरवरी 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1591/क/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	पकरिया	1.292 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-03-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत पकरिया नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत भूमि अर्जन
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	- लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	आवागमन की सुविधा हेतु
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सरगुजा, दिनांक 3 मार्च 2022

रा.प्र.क्रमांक/177/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	सलका	3.109	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पतराटोली जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग**

रायगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 294/1202010042200060/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	महाराजगंज प.ह.नं. 46	0.045	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	महाराजगंज से भुण्डी-बहरी पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 301/01/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बायसी प.ह.नं. 36	0.397	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	नरकालो से बायसी पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 305/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बेहरामुड़ा प.ह.नं. 58	1.278	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तेन्दुमुड़ी से बेहरामुड़ा पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 310/02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कोयलार प.ह.नं. 35	0.040	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	नरकालो से बायसी पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (अम्बिकापुर),
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

सरगुजा, दिनांक 19 जनवरी 2022

क्रमांक/61/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-लखनपुर
(ग) नगर/ग्राम-लोसंगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.929 हेक्टेयर

320/14	0.849
320/391	0.405
320/13	0.101
320/25	0.205
320/7	0.089
70/17	0.052
320/17	0.066
41	0.072
52/1	0.093
34/17	0.069
46	0.025
56/1	0.032
83/1	0.102
80/7	0.049
71	0.061
70/18	0.096
69/340	0.098
73/1	0.024
40	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
278	0.016	70/16	0.086
314/3	0.101	300	0.128
302	0.045	302/2	0.085
276	0.012	303/1	0.052
257/4	0.250	301/2	0.056
157/396	0.023	261	0.040
320/15	0.234	157/395	0.077
314/7	0.243	157/404	0.236
320/347	0.113	157/405	0.058
320/23	0.052	157/382	0.045
320/6/1	0.128	320/12	0.024
320/345	0.048	333/1	0.062
5/3	0.072	242/1	0.034
14	0.096	157/403	0.042
34/4	0.144	153/381/1	0.084
35/7/1	0.080	230	0.079
47/3/2	0.020	230/333/2	0.008
56/2	0.032	157/387/2	0.102
82/1	0.048	491	0.724
80/1	0.049	228/1	0.235
66	0.109	227	0.223
70/14	0.310		
73/3	0.024	योग	88 9.929
81/2	0.164		
314/5	0.058		
279	0.034		
262	0.045		
260	0.027		
259	0.008		
157/394	0.134		
157/402	0.128		
320/16	0.526		
320/35	0.220		
39	0.045		
320/12	0.102		
320/509	0.128		
320/4	0.048		
5/5	0.253		
12/1	0.168		
34/2	0.067		
35/7/2	0.096		
43/1/2	0.016		
56/3	0.032		
80/359	0.058		
78	0.069		
70/6	0.117		
70/15	72		
73/2	0.024		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोसंगा जलाशय योजना के डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 22 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 77/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/11-अ/82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		16/2	0.03
(क) जिला-महासमुन्द		13	0.03
(ख) तहसील-सरायपाली		477	0.01
(ग) नगर/ग्राम-कनपला, प.ह.नं. 26		641/2	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर		16/1	0.05
		18	0.37
		8	0.87
खसरा नम्बर	रकबा	479	0.08
	(हेक्टेयर में)	478	0.05
(1)	(2)	476	0.02
		456	0.02
377	0.10	455	0.01
447/1	0.06	545	0.13
447/2	0.06	367/2	0.28
		468	0.06
योग	3	441/1	0.05
		368	0.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनपला		53	0.12
व्यपवर्तन योजना के दांयी नहर निर्माण हेतु.		56	0.07
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		371	0.05
(रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.		24	0.02
		542	0.04
		25	0.02
महासमुन्द, दिनांक 23 फरवरी 2022		26/1	0.06
		29/2	0.02
प्रकरण क्रमांक 79/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/09-अ-82/वर्ष		31	0.07
2019-20.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है		32	0.02
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के		30	0.02
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.		58	0.06
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर		531	0.04
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्		59	0.05
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा		60	0.02
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए		57	0.02
आवश्यकता है :-		467	0.07
अनुसूची		440	0.05
		439	0.01
		370	0.04
(1) भूमि का वर्णन-		373	0.09
(क) जिला-महासमुन्द		369/2	0.06
(ख) तहसील-सरायपाली		348	0.04
(ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प.ह.नं. 05		349	0.13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टेयर		530	0.02
		350	0.05
खसरा नम्बर	रकबा	457/2	0.06
	(हेक्टेयर में)	480/1	0.03
(1)	(2)	357/2	0.07
		357/1	0.05
12	0.05	356/2	0.02

(1)	(2)
358/1	0.03
464/3	0.04
64	0.01
15	0.03
641/1	0.02
441/2	0.18
योग	55
	4.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्राभांठा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 80/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/08-अ/82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-सिरपुर, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55	0.07
98	0.18
59	0.08
61	0.05
62	0.06
64	0.06
67/1	0.06
67/2	0.05

(1)	(2)
68	0.11
118	0.01
135	0.04
136	0.01
134	0.05
133/2	0.01
133/3	0.06
133/4	0.04
132	0.04

योग 17 0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनपला व्यपवर्तन योजना के दांयी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 81/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/07-अ/82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कालीदरहा, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471	0.06
475	0.15
458	0.02
459	0.01

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुड़ जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
454	0.01	
455	0.03	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.
452/4	0.08	
योग	07	0.36

महासमुन्द, दिनांक 24 फरवरी 2022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटंगी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 82/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/12-अ/82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

प्रकरण क्रमांक 87/क/कलेक्टर/भू-अर्जन/06-अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-जोगीडीपा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.29 हेक्टेयर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(क) जिला-महासमुन्द		(1)	(2)
(ख) तहसील-सरायपाली		2	0.49
(ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प.ह.नं. 42		8	0.36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर		82	0.04
		103	0.11
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	184/1	0.60
(1)	(2)	315	0.01
		316	0.06
		353	0.16
		374/1	0.64
1133	0.02	9/1	0.06
1135/1	0.06	13/5	0.07
1136/1	0.07	13/13	0.03
1154	0.09	9/2	0.01
1138	0.01	13/8	0.02
1040	0.04	11/2	0.05
		12/1	0.01
योग	6	12/2	0.05
		13/6	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
13/14	0.08	180	0.12
13/7	0.08	83/4	0.03
13/9	0.10	314	0.04
13/16	0.01	351/1	0.05
31/2	0.16	351/2	0.05
31/5	0.10	374/3	0.01
31/4	0.04	374/4	0.08
31/6	0.02		
88	0.07	योग	43
85/1	0.05		4.29
85/2	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरकोट	
85/3	0.10	व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.	
85/8	0.03	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
69/3	0.01	(रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.	
85/7	0.03	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
83/3	0.06	नीलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
83/5	0.01		
83/6	0.06		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 25 फरवरी 2022

क्रमांक/स्था./2022/1797.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-01/2022/10-(भा.व.से.) दिनांक 21-02-2022 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 25-02-2022 को पूर्वान्ह/अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

No. /स्था./2022/1797.— Certified that in according with the PCCF Raipur to Order No. F 1-01/2022-10-(IFS) Date 21-02-2022 Shri Aravind P.M. (I.F.S.) Make over to Shri Alok Kumar Bajpayee (I.F.S.) Charge of the D.F.O. Kanker on Noon/Afternoon Dated 25-02-2022 that the office receiving charge.

आलोक कुमार बाजपेयी,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक/2355/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर कोरबा को पूर्व में सौंपे गये कार्यों के साथ-साथ निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- लायसेंस
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक/2357/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा को पूर्व में सौंपे गये कार्यों के साथ-साथ निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- परीक्षा शाखा
- वरिष्ठ लिपिक एवं अति वरिष्ठ लिपिक
- मुख्यमंत्री घोषणा
- भू-बंटन
- आवक जावक
- बैंक से संबंधित समस्त कार्य (लीड बैंक नोडल)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
- 20 सूत्रीय 15 सूत्रीय
- दंगा पीड़ित 1984
- जिला पर्यावरण संरक्षण मण्डल (पर्यावरण)
- यातायात जिला सड़क सुरक्षा

नोडल अधिकारी :—

- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
- जल संसाधन विभाग
- सार्वजनिक उपक्रमों से समन्वय संबंधी कार्य
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रानू साहू,
कलेक्टर.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6093.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5258-5259 दिनांक 16-12-2021 द्वारा श्री विनायक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर जिला बालोद, को कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर जिला बालोद (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/223/वि.लि. 1/स्था./2022 दिनांक 11-01-2022 द्वारा श्री रामसिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जिला बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला बालोद का नाम भारसाधक अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री विनायक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर, जिला बालोद के स्थान पर श्री रामसिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जिला बालोद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6095.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/3902-3903 दिनांक 25-08-2018 द्वारा श्री आर.एस. कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बम्हनीडीह को कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला जांजगीर चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/16622/स्थापना/2021 दिनांक 29-12-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति चांपा के भारसाधक अधिकारी श्री आर.एस. कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बम्हनीडीह दिनांक 30-11-2021 को सेवानिवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री के. पी. कश्यप प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी, बम्हनीडीह को कृषि उपज मंडी समिति चांपा, जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री आर.एस. कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बम्हनीडीह के स्थान पर श्री के. पी. कश्यप प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी, बम्हनीडीह को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6381.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/1805 दिनांक 24-06-2019 द्वारा श्री एल.एम. भगत, उप संचालक कृषि, रायगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला रायगढ़ का पत्र क्रमांक क्र/मंडी/भा.अधि./2021-22/476 दिनांक 22-01-2022 द्वारा श्री एल.एम. भगत, उप संचालक कृषि रायगढ़ का स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर, उप संचालक कृषि रायगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री एल.एम. भगत, उप संचालक कृषि रायगढ़ के स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर, उप संचालक कृषि रायगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6383.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/3143 दिनांक 04-09-2021 द्वारा श्री पेखन टोण्ड्रे, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर हेतु कलेक्टर बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक क/वित्त-1/2022/354 दिनांक 28-01-2022 द्वारा श्री पेखन टोण्ड्रे, नायब तहसीलदार तखतपुर का दिनांक 23-12-2021 को स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री शशांक शेखर शुक्ला, तहसीलदार तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री पेखन टोण्ड्रे, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार, तखतपुर के स्थान पर श्री शशांक शेखर शुक्ला, तहसीलदार तखतपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6488.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5979 दिनांक 22-01-2022 द्वारा श्री यू.एस. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति रायपुर, जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/998/वित्त/वि.लि./2022 दिनांक 08-02-2022 द्वारा श्री यू.एस. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर रायपुर के स्थान पर श्री मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति रायपुर, जिला रायपुर के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री यू.एस. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर रायपुर के स्थान पर श्री मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायपुर, जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6494.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6095 दिनांक 29-01-2022 द्वारा श्री के.पी. कश्यप, प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी, बम्हनीडीह को कृषि उपज मंडी समिति चांपा, जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/1777/स्थापना/2022 दिनांक 07-02-2022 द्वारा श्री के.पी. कश्यप, प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी बम्हनीडीह चांपा के स्थान पर श्री के.आर. पाटले, कृषि विकास अधिकारी बम्हनीडीह को कृषि उपज मंडी समिति चांपा, के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री के.पी. कश्यप, प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी, बम्हनीडीह के स्थान पर श्री के.आर. पाटले, कृषि विकास अधिकारी बम्हनीडीह को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति चांपा, जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/6498.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/4515 दिनांक 02-12-2020 द्वारा श्री नवीन कुमार भगत, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी, जिला मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर हेतु कलेक्टर, मुंगेली (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/7982/व.लि./2021 दिनांक 21-12-2021 द्वारा श्री नवीन कुमार भगत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती मेनका प्रधान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री नवीन कुमार भगत, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी, जिला मुंगेली के स्थान पर श्रीमती मेनका प्रधान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 24 मार्च 2022

शुद्धि पत्र

क्रमांक/1037/न.ग्रा.नि./2022.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5014/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2021 बिलासपुर दिनांक 16-12-2021 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन जारी सूचना जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में भाग-1, पृष्ठ क्र. 115 में दिनांक 04-02-2022 को मुद्रित हुई है, में पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग के स्थान पर पुनर्गठित पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम अमरपुर एवं लटकोनीकला के लिए वर्तमान भूमि उपयोग पढ़ा जावे.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 3/L.G./2022/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 01 day on 18-10-2021 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 12-10-2021 till 18-10-2021, earned leave for 10 days from 23-12-2021 to 01-01-2022 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 22-12-2021 till before the office hours of 03-01-2022 and earned leave for 04 days from 21-02-2022 to 24-02-2022 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 18-02-2022 till before the office hours of 25-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 4/L.G./2022/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 06 days from 31-01-2022 to 05-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 05/L.G./2022/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, District & Sessions Judge, Bemetara, is hereby, granted earned leave for 02 days on 04-02-2022 & 05-02-2022 along with permission to remain out of headquarters from 04-02-2022 to 06-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 182 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 06/L.G./2022/II-2-32/2015.—Shri Omprakash Singh Chauhan, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 09 days from 14-01-2022 to 22-01-2022 and earned leave for 06 days from 03-02-2022 to 08-02-2022 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chauhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 215 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 07/L.G./2022/II-3-28/2008.—Smt. Girija Devi Meravi, Judge, Family Court, Balod is hereby, granted earned leave for 09 days from 07-02-2022 to 15-02-2022 along with permission to leave headquarters from 06-02-2022 to 15-02-2022.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Meravi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 261 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 08/L.G./2022/II-2-26/2017.—Smt. Shraddha Shukla Sharma, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 22-11-2021 to 24-11-2021 along with permission to remain out of headquarters, commuted leave for 35 days from 25-11-2021 to 29-12-2021 and child care leave for 10 days from 24-02-2022 to 05-03-2022.

During the period of earned leave, commuted leave & child care leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 208 days of earned leave, 193 days of half-pay-leave & 720 days of child care leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 09/L.G./2022/II-3-30/2008.—Shri Mohd. Rizwan Khan, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted commuted leave for 04 days from 04-01-2022 to 07-01-2022 and commuted leave for 03 days from 16-02-2022 to 18-02-2022.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Khan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 178 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 10/L.G./2022/II-2-37/2005.—Shri Shailesh Kumar Ketarap Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 05 days from 27-12-2021 to 31-12-2021 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 24-12-2021 till the morning of 01-01-2022 and earned leave for 05 days from 14-02-2022 to 18-02-2022 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 11-02-2022 till the morning of 21-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ketarap, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 11/L.G./2022/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 13 days from 24-01-2022 to 05-02-2022 and earned leave for 05 days from 14-02-2022 to 18-02-2022 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 11-02-2022 till before the Court hours of 21-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 12/L.G./2022/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar Prasad, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 07 days from 20-12-2021 to 26-12-2021 with winter vacation along with permission to leave headquarters after the office hours of 17-12-2021 till before the office hours of 01-01-2022 and earned leave for 05 days from 07-02-2022 to 11-02-2022 along with permission to leave headquarters after the office hours of 05-02-2022 till before the office hours of 14-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prasad, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 13/L.G./2022/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 06 days from 27-12-2021 to 01-01-2022 along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 to 02-01-2022 and earned leave for 09 days from 12-01-2022 to 20-01-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd March 2022

No. 14/L.G./2022/II-3-14/2014.—Ms. Sanghratna Bhatpahari, Special Judge (Atrocities), Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 03-02-2022 to 05-02-2022 along with permission to remain out of head-quarters after the Court hours of 02-02-2022 till before the Court hours of 07-02-2022.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Ms. Bhatpahari, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)

Bilaspur, the 9th March 2022

No. 15/L.G./2022/II-3-11/2010.—Shri Awadh Kishore, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 06-01-2022 to 14-01-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kishore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
DAVENDER KUMAR, Additional Registrar (D.E. & E.)